

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'राजस्थान राजस्व मंडल में नियुक्ति व सेवा शर्त संबंधी' नए नियम
2.	राजस्थान की स्कूटी वितरण योजनाओं में संशोधन
3.	राजीविका कार्यकारी समिति की 21वीं बैठक
4.	राजस्थान रॉयल्स का 'पिंक प्रॉमिस' मैच
5.	वृक्ष मित्र सम्मान समारोह - 2026
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान के मुख्य सचिव की यूनिसेफ की प्रतिनिधि के साथ बैठक
7.	वाडिनार
8.	पुलित्जर पुरस्कार
9.	केयर इकोनॉमी/ पर्पल इकोनॉमी
10.	इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs)
11.	2026-27 सीज़न के लिए गन्ने के लिए FRP
12.	राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971
13.	UDGAM पोर्टल
14.	विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2026 (World Migration Report)

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



'राजस्थान राजस्व मंडल में नियुक्ति व सेवा शर्त संबंधी' नए नियम



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा राजस्व विभाग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नए नियम लागू किए गए।



मुख्य बिन्दु:

- नियम :** राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 4(4) तथा धारा 261(2)(i) के तहत बनाए गए हैं।
- नए नियमों के अनुसार राजस्व मंडल द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त होने वाले अधिकारियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने का प्रावधान किया गया है, वहीं अधिवक्ताओं के लिए पेंशन को ₹50,000 करने का निर्णय लिया है।
- अध्यक्ष :** नए नियमों के अनुसार राजस्व विभाग में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले IAS के लिए न्यूनतम अनुभव 13 वर्ष से बढ़ा 16 वर्ष अनिवार्य किया गया है।
- सदस्य :** 20 सदस्यीय बोर्ड में 09 सदस्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (RAS), दो न्यायिक सेवा एवं दो अधिवक्ता होंगे। शेष पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।
- कार्यकाल :** अध्यक्ष एवं सदस्य अपने मूल सेवा कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। पुनर्नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- विशेष भत्ता :** नए नियमों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को मूल वेतन के अलावा 15 प्रतिशत विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह लाभ कार्यकाल या सेवानिवृत्ति तक लागू रहेगा।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



- अधिवक्ता कोटे से नियुक्त सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो तथा कम से कम 1 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिलेगी। पेंशन राशि को पूर्व के ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। अधिवक्ता सदस्य 4 वर्ष या 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक बनाए जा सकेंगे।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्व मंडल भूमिका :-

श्रेणी	विवरण
प्रकृति	अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body) और राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय।
मुख्यालय	अजमेर (सर्किट बेंच : जयपुर)
प्रमुख कार्य	राजस्व वादों की अपील, पुनरीक्षण (Revision), भू-अभिलेखों का रखरखाव और बंदोबस्त।
उद्देश्य	किसानों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना तथा बिचौलियों का अंत करना।
संरचना	इसकी संरचना 1+20 हैं। सदस्य न्यूनतम 3 व अधिकतम 20 हो सकते हैं।
सेवा शर्तें	राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर बदलाव।

- राजस्थान में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक एवं नियंत्रक के रूप में राजप्रमुख के अध्यादेश के द्वारा राजस्व मण्डल की स्थापना 1 नवंबर, 1949 को हुई।
- वर्ष 1956 में उक्त अध्यादेश के स्थान पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 लागू किया गया। राजस्व मण्डल राजस्व मामलों में राज्य का शीर्षस्थ अपील, पुनर्विलोकन एवं सन्दर्भ राजस्व न्यायालय हैं, जिसको तीन प्रकार से अधिकार प्राप्त है -

--3--

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



1. अपील।

2. पुनर्विचार।

3. रैफरेंसेज।

- इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल द्वारा भू-अभिलेख संधाता के पर्यवेक्षण का कार्य भी किया जाता है, जो न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्य है।
- **नोट :** सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर नवम्बर, 1958 में राजस्व मण्डल को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया।

राजस्व मण्डल का प्रशासनिक ढाँचा :-

- इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसकी सहायता हेतु 20 सदस्य होते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा व राजस्व मामले के विशेषज्ञ वकीलों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

सदस्य	योग्यता
भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	राजस्थान कैडर का अधिकारी, जो कम से कम 16 वर्ष राज्य में कार्य कर चुका हो।
राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।
अधिवक्ता	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।
राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग	सुपर टाइम स्केल श्रृंखला।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :

- राजस्थान राजस्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष : बृजचन्द शर्मा।
- वर्तमान अध्यक्ष : अजिताभ शर्मा।
- प्रथम राजस्व दिवस : 15 अक्टूबर, 2020
- राजस्थान राजस्व परिषद् का गठन : वर्ष 1953 में।

--:4:--

राजस्थान की स्कूटी वितरण योजनाओं में संशोधन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी वितरण की 2 प्रमुख योजनाओं 'कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना' और 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना' में संशोधन किए जाने की अधिसूचना जारी की।

मुख्य बिन्दु:

- अधिसूचना के अनुसार, पात्र छात्राओं को भौतिक रूप से स्कूटी देने के बजाय सीधे उनके बैंक खातों में ₹70,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।

योजनाओं के बारे में:

योजना का नाम	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना
संबंधित विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग
योजना की शुरुआत	2015-16	2023
पात्र श्रेणी	GEN/OBC/EWS/SC/ST अल्पसंख्यक छात्रा।	अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं (जैसे - बंजारा, गाड़िया लुहार, राईका, रेबारी, देवासी आदि)
पात्र लाभार्थी	कक्षा 12 में : RBSE में न्यूनतम 65 प्रतिशत और CBSE में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।	कक्षा 12 में : RBSE और CBSE में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



	नोट : उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना अनिवार्य।	नोट : उच्च शिक्षा के प्रथम वर्ष में प्रवेश और नियमित होना अनिवार्य।
परिवार की वार्षिक आय	₹2.5 लाख से कम।	₹2.5 लाख से कम।
अन्य बिन्दु	अधिकतम स्कूटी संख्या : 30000	अन्य प्रोत्साहन : स्नातक (UG) के तीनों वर्षों में ₹10,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त सहायता। स्नातकोत्तर (PG) के दो वर्षों में ₹20,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त सहायता।

--6--

राजीविका कार्यकारी समिति की 21वीं बैठक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में जयपुर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की 21वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य बिन्दु:

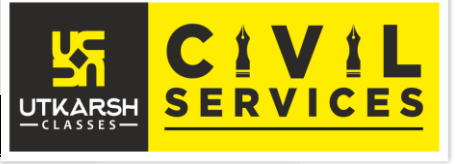
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (RGAVP) या राजीविका की स्थापना वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
- यह राजस्थान सोसायटी अधिनियम - 1958 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- **अध्यक्ष** : मुख्यमंत्री।

उद्देश्य:

- ग्रामीण विकास के लिए की जा रही सरकारी और गैर-सरकारी पहलों के बीच प्रभावी अभिसरण लाना।
- स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के गठन और सुदृढीकरण में सहायता करना।
- गरीबों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना।
- **राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में राजीविका** : राज्य में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



राजीविका द्वारा कार्यान्वित और संचालित योजनाएँ और मिशन:

- राजस्थान रूरल लाईवलीहुड परियोजना (RRLP)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- द मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (MPOWER)
- नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट (NRETP)
- वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट (OBOP)
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRLP)
- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना।
- बर्तन बैंक योजना।
- मिशन समृद्ध दीदी
- वन धन विकास केंद्र
- 'लखपति दीदी' पहल आदि।

--8--

राजस्थान रॉयल्स का 'पिंक प्रॉमिस' मैच

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान रॉयल्स (RR) द्वारा 9 मई, 2026 को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में 'पिंक प्रॉमिस' मैच खेला जाएगा।



मुख्य बिन्दु:

- इस मैच के दौरान लगने वाले हर एक सिक्स पर 6 ग्रामीण घरों को सोलर पैनल के जरिए रोशन किया जाएगा। इसके तहत सांभर (जयपुर) में घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
- जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में 'मीट एंड ग्रीट' कार्यक्रम के दौरान 'पिंक प्रॉमिस जर्सी' लॉन्च की गई।
- उद्देश्य :** यह पहल 'रॉयल राजस्थान फाउंडेशन' (RRF) द्वारा ग्रामीण राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है।
- पहल के तहत 5वीं पास महिलाओं को 5 महीने की ट्रेनिंग देकर 'सोलर इंजीनियर' बनाया गया है, जिनमें 20 महिलाएं कार्य कर रही हैं।

--9--

वृक्ष मित्र सम्मान समारोह - 2026

चर्चा में क्यों?

- श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा 31वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर जयपुर में 'वृक्ष मित्र सम्मान समारोह - 2026' का आयोजन किया गया।



--:10:--



मुख्य बिन्दु:

- **मुख्य अतिथि** : अभिनेत्री रवीना टंडन।
- समारोह के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर 2.0' अभियान का द्वितीय संस्करण लॉन्च किया गया एवं परिंदों के लिए 'परिंडा अभियान' शुरू किया गया।

सम्मानित व्यक्तित्व:

- अलवर के त्रिलोकी नाथ शर्मा को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रथम।
- कोटा पुलिस की सब इंस्पेक्टर उमा विकास को वृक्ष मित्र पुरस्कार द्वितीय।
- प्रतिदिन एक पौधा लगाने वाली उषा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार तृतीय।
- **विशेष पुरस्कार** : 'ग्रीन बचपन अभियान' का नेतृत्व कर रही विवेन पारीक को 'वालंटियर ऑफ द ईयर' पुरस्कार।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- श्री कल्पतरु संस्थान जयपुर में स्थित एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो 31 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सक्रिय है।
- **संस्थापक** : इसकी स्थापना विष्णु लांबा ने की थी, जिन्हें पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण के कारण 'ट्री मैन ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राजस्थान के मुख्य सचिव की यूनिसेफ की प्रतिनिधि के साथ बैठक</p> <ul style="list-style-type: none">■ 6 मई, 2026 को राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।■ बैठक में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, महिला एवं बाल विकास, पोषण, शिक्षा तथा बाल अधिकार संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।■ आगामी कार्ययोजना (2026-29) : सिंथिया मैककैफ्रे ने यूनिसेफ की वर्ष 2026-29 की कार्ययोजना साझा की, जिसके तहत नीति निर्माण, तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में यूनिसेफ की भूमिका को और सशक्त बनाया जाएगा।

CIVIL SERVICES

राष्ट्रीय परिदृश्य

वाडिनार

चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुजरात के वाडिनार में एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र के विकास को मंजूरी प्रदान की।



मुख्य बिन्दु:

- इस परियोजना को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।
- इसे एक ब्राउनफील्ड सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा।
- वाडिनार को चुनने का कारण: प्राकृतिक रूप से गहरा समुद्री तट उपलब्ध होना, प्रमुख बंदरगाहों के पास स्थित होना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होना।

पुलित्जर पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- दो भारतीय पत्रकारों आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ने भारत में साइबर अपराध को उजागर करने के लिए 'इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री' श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता।



मुख्य बिन्दु:

पुलित्जर पुरस्कार

- परिचय:** यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह रिपोर्टिंग और स्टोरी-टेलिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है।
- यह अमेरिका में पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह प्रतिवर्ष 23 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है।
- प्रशासक:** कोलंबिया विश्वविद्यालय।
- इसे 1917 में हंगेरियन-अमेरिकी समाचार-पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के अनुसार शुरू किया गया था।

आर्थिक घटनाक्रम

केयर इकोनॉमी/ पर्पल इकोनॉमी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने केयर इकोनॉमी पर वर्किंग पेपर जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

- इस वर्किंग पेपर में 'देखभाल' यानी 'केयर' को निजी घरेलू जिम्मेदारी के बजाय एक मूलभूत सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के रूप में मानने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

केयर इकोनॉमी

- इसे 'पर्पल इकोनॉमी' भी कहा जाता है।
- इसमें बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए आवश्यक कार्य (सवैतनिक या अवैतनिक) शामिल हैं।

- **जीडीपी में योगदान:** अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य (मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला) का मूल्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 15-17% के बराबर है।

EAC-PM की सिफारिशें

नवाचारी वित्तपोषण व्यवस्था:

- **परिवार सेवा कोष की स्थापना:** इससे समुदाय द्वारा संचालित देखभाल अवसंरचनाओं और सेवाओं को वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- **केयरप्रेन्योर फंड:** केयर इकोनॉमी क्षेत्रक के उद्यमियों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी का लाभ उठाना:** जैसे, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित तमिलनाडु का "महिला रोजगार और सुरक्षा कार्यक्रम", जिसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- **केयर वर्कफोर्स तैयार करना:** आवश्यक कौशल में कमी का आकलन करना चाहिए तथा मानकीकृत प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने चाहिए।

नीतिगत सुधार:

- **लैंगिक-तटस्थ यानी महिलाओं और पुरुषों को चाइल्डकेयर अवकाश:** चरणबद्ध सुधार के तहत पितृत्व अवकाश को निजी क्षेत्र में भी लागू करना चाहिए।
- **शहरी योजना में समावेशन:** देखभाल से जुड़ी सुविधाओं को आवश्यक सामाजिक अवसंरचना के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।
- **मातृत्व लाभ की सुविधा को सुदृढ़ करना:** उदाहरण के लिए, सिक्किम में निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली माताओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह मॉडल देश भर में लागू किया जा सकता है।

अन्य:

- देखभाल सहकारी समितियों के गठन का समर्थन किया गया है।
- सरकारी स्कूलों के भीतर ही बाल-देखभाल केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए।
- गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs)



चर्चा में क्यों?

- भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत के स्वर्ण बाजार को औपचारिक रूप देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGRs) की शुरुआत की।



मुख्य बिन्दु:

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2022 में EGR की शुरुआत करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था।

EGRs

- ये डिमैट प्रतिभूतियां होती हैं, जो भौतिक स्वर्ण के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह स्वर्ण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है और डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है।
- EGR को कभी भी भौतिक स्वर्ण के रूप में बदला जा सकता है, जबकि गोल्ड ETF का आमतौर पर नकद में सेटलमेंट होता है।
- **विनियामक:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)।
- **परिसंपत्ति की श्रेणी:** प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956 के तहत प्रतिभूतियां।

--:17:-

2026-27 सीज़न के लिए गन्ने के लिए FRP

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 10.25% वसूली दर के साथ 2026-27 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।



मुख्य बिन्दु:

उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

- FRP सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिसके तहत चीनी मिलें किसानों को उनकी उपज के लिए भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।
- गन्ने के लिए उचित प्रतिफल (FRP) का निर्धारण प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



- देशभर में FRP का भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें गन्ने की डिलीवरी की तारीख से 14 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है, ऐसा न करने पर गन्ना आयुक्त मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
- किसानों का बकाया न चुकाने पर मिल की संपत्तियों को जब्त भी किया जा सकता है।

तंत्र

- गन्ने के लिए FRP का निर्धारण उसी प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है जिसका उपयोग 23 अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गणना के लिए किया जाता है।
- हालांकि, MSP की कानूनी रूप से गारंटी नहीं है, लेकिन चीनी मिलें FRP का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- FRP विधि गन्ने से चीनी निकालने की प्रक्रिया पर आधारित है।
- गन्ने की पिसाई और उत्पादित चीनी का अनुपात शुगर रिकवरी कहलाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

--:19:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य:** राष्ट्रगान वंदे मातरम के गायन में किसी भी प्रकार का अपमान या बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध बनाना।
- वर्तमान में, भारत के राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान करना 1971 के अधिनियम में उल्लिखित है और इसके लिए तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।

वंदे मातरम

- वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी और यह पहली बार 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ में दिखाई दिया था।
- आनंदमठ की कहानी 1769-73 के बंगाल के अकाल और संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
- रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाए जाने से इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।
- 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान, वंदे मातरम नागरिक प्रतिरोध के राष्ट्रगान के रूप में उभरा।
- वंदे मातरम का राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार प्रयोग 7 अगस्त 1905 को किया गया था।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



- **राष्ट्रीय गीत:** 24 जनवरी, 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 51ए(ए) मौलिक कर्तव्य:** प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का आदेश देता है।
- **स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण का अभाव:** राष्ट्रगान के विपरीत, वंदे मातरम किसी भी संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है।
- इसकी स्थिति संविधान सभा के प्रस्तावों से निर्धारित होती है, न कि लागू करने योग्य संवैधानिक पाठ से।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:21:-

योजनाएँ एवं नीतियाँ

UDGAM पोर्टल

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 30 बैंकों को UDGAM पोर्टल में एकीकृत कर लिया गया है।



मुख्य बिन्दु:

UDGAM पोर्टल

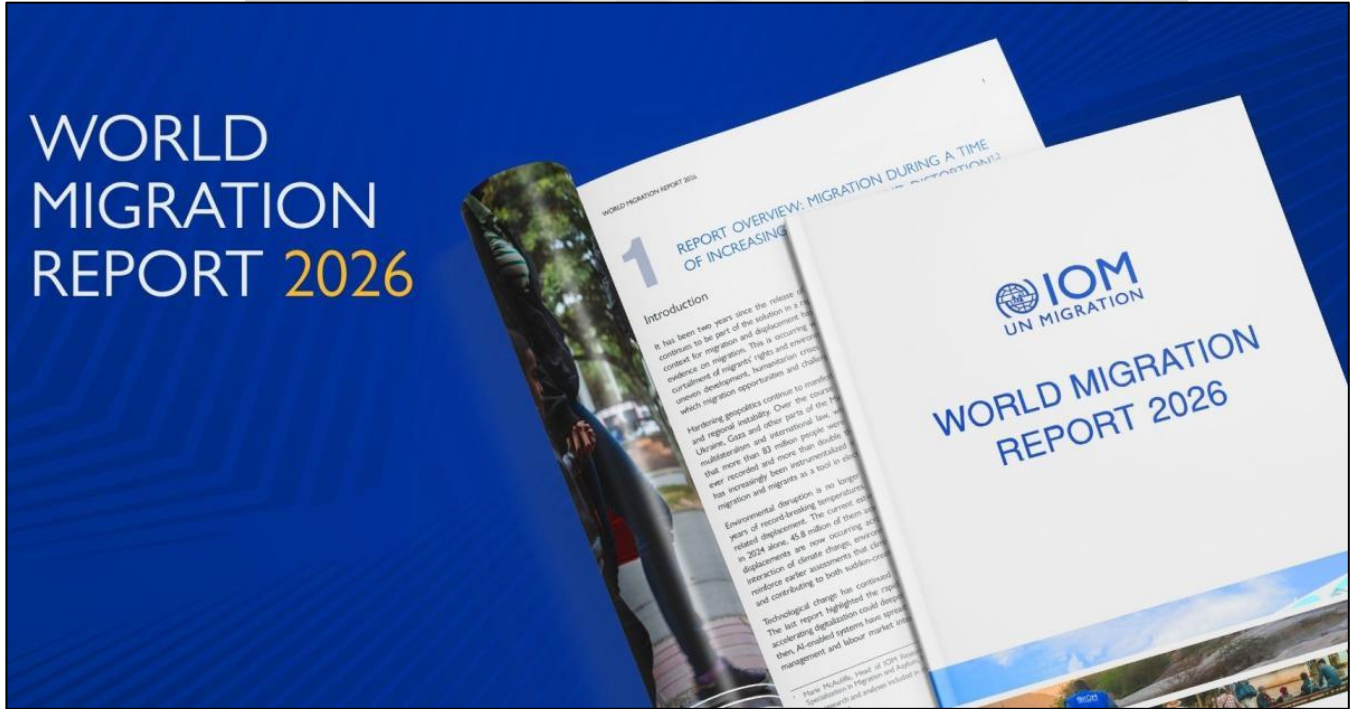
- UDGAM (अदावाकृत जमा - सूचना तक पहुंच का द्वार) पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है ताकि अदावाकृत बैंक जमाओं के लिए एक केंद्रीकृत खोज सुविधा प्रदान की जा सके।
- यह नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई भागीदार बैंकों में लावारिस शेष राशि की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- यह पोर्टल दावों का निपटारा नहीं करता है; बल्कि, यह उपयोगकर्ताओं को उन संबंधित बैंकों तक निर्देशित करके प्रक्रिया को सुगम बनाता है जहां जमा राशि रखी जाती है।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

विश्व प्रवासन रिपोर्ट, 2026 (World Migration Report)

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 जारी की।



मुख्य बिन्दु:

- **वैश्विक प्रवासन:** 2024 में लगभग 304 मिलियन लोग अपने जन्म वाले देश से बाहर रह रहे थे, जो वैश्विक आबादी का 3.7% है, जबकि 1990 में यह 2.9% था।
- **शीर्ष प्रवास मार्ग:** मैक्सिको-USA (पहला), अफगानिस्तान-ईरान (दूसरा), सीरिया-तुर्की (तीसरा), रूस-यूक्रेन (चौथा), भारत-UAE (पांचवां) और भारत-USA (छठा)।
- **विकास को गति देने वाला प्रवासन:** 2024 में वैश्विक स्तर पर विप्रेषण अनुमानतः 905 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजे गए 685 बिलियन डॉलर शामिल हैं।

Daily Current Affairs

Date : 07 May, 2026



भारत से संबंधित:

- UAE में भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 मिलियन से अधिक थी, जबकि USA में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 3.2 मिलियन (मैक्सिकन प्रवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या) थी।
- भारत में पुरुष अप्रवासियों की तुलना में महिला अप्रवासियों की हिस्सेदारी अधिक थी।
- भारत से पुरुषों का प्रवासन मुख्य रूप से खाड़ी देशों आदि में श्रम प्रवासन के कारण हुआ है।



--:24:--